जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:235 दिनांक:05-08-2024 सोमवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

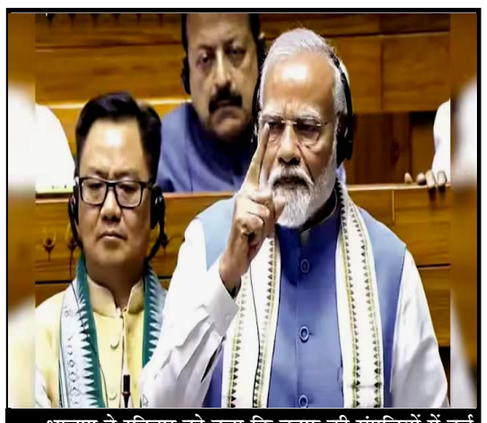

भाजपा ने रविवार को कहा कि वक्फ की संपत्तियों में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है। भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार को वक्फ संपत्तियों की अनियमितताओं को दूर करना होगा ।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए आगामी भारत-अमेरिका मिशन के वास्ते चुना गया है।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में सरकार

-किसी जमीन को अपनी संपत्ति बताने पर रोक लगेगी

नई दिल्ली(ईएमएस)। केन्द्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट को संशोधन वाला एक नया बिल लेकर आ सकती है। सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। नए बिल में वक्फ की किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है।

सूत्रों को मुताबिक शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट के कुछ क्लॉस को हटाया भी जा सकता है। संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है।

ड्राफ्ट बिल में ये बड़े बदलाव किए जा सकते हैं

किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया जाएगा। जिससे केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है।

नए बिल से वक्फ बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा

वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था है। नए संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

वक्फ बोर्ड से जुड़े पुराने घटनाक्रम

वक्फ बोर्ड से जुड़े नए बिल के पीछे सितंबर 2022 के एक मामले का तर्क दिया जा रहा है। जिसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदुर गांव को अपनी संपत्ति बताया था। जिसमें रहने वाली ज्यादातर आबादी हिंदू है। पिछले साल मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में उन 123 संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा है। पिछले साल अगस्त में ही केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। मोदी सरकार 2.0 के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किसी विशेष संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उनके मुतवल्लियों की नियुक्ति के प्रोसेस

कोरबा एक्सप्रेस की 4 बोगियों में लगी आग

विशाखापट्टनम(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ के कोरबा से विशाखापट्टनम पहुंची कोरबा एक्सप्रेस (18517) ट्रेन की बोगियों में रविवार को अचानक से भीषण आग लग गई। यह ट्रेन कोरबा से तिरुमाला जा रही थी। जब ट्रेन स्टेशन पर रूकी तो इसी दौरान इसमें अचानक से आग लग गई। आग लगने की यह घटना स्टेशन के चौथे नंबर के प्लेटफॉर्म पर हुई। इस दौरान तीन एसी बोगियां पूरी तरह जल गई हैं।

हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की यह घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। रेलवे अधिकारियों ने शुरू में पाया कि यह दुर्घटना बी7 बोगी के शौचालय में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। नतीजतन, बी7 बोगी पूरी तरह जल गई, जबकि बी6 और एम1 बोगियां आंशिक रूप से जल गईं हैं,। गनीमत यह रही कि घटना के समय ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से कई मकान व वाहन बहे, नुकसान की जानकारी नहीं

-श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, नुकसान का आकलन करने अधिकारी मौके पर पहुंचे

श्रीनगर,(ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में रविवार को बादल फटा गया जिसमें कई मकान और गाड़ियां बह गई। मलबा रोड पर आने से श्रीनगर नेशनल हाईवे और श्रीनगर-कारगिल रोड बंद कर दिया गया है। कवचरवान, चेरवा और पडबल गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जिससे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। कई मकान और वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से आई बाढ़ मकानों समेत कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। वहीं मई माह में भी बादल फटने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। लोगों को मदद देने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संपर्क कट गया है जबकि अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल शिविर जाना भी दुर्गम हो गया है। नुकसान का आकलन करने अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों मुताबिक कंगन, गांदरबल में बादल फटने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।

दूसरी तरफ मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में पिछले तीन दिन से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के दस बड़े डैमों में पानी ओवरफ्लो हो गया है जिसके चलते डैमों के गेट खोल दिए गए थे। राज्य में 21 जून को मानसून की दस्तक के बाद से अब तक 58फीसदी यानी 21.6 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 2.6 इंच ज्यादा बारिश हो चुकी है।

वहीं राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 21फीसदी ज्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में आमतौर पर एक जून से तीन अगस्त तक 231.3मिमी औसत बरसात होती है, जबकि इस सीजन में अब तक 280.6मिमी बरसात हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों में बादल फटने की घटनाओं के कारण 114 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने राज्य में सात अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है और यलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 27 जून से एक अगस्त के बीच बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड में 79 लोगों की मौत हुई है।

2 करोड़ अमेरिका में निवेश करो, 5 लोगों के साथ 5 साल रहो, भारतीयों के लिए अमेरिका की नई स्कीम

नई दिल्ली (ईएमएस) । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन स्टार्टअप एंड स्टे नामक स्कीम लाए हैंइस स्कीम में जो भी भारतीय नागरिक 2 करोड रुपए का निवेश स्टार्टअप के रूप में अमेरिका में करेगा। उसको अमेरिका में 5 साल तक रहने की अनुमति मिलेगी। निवेशक को पति-पत्नी और तीन कर्मचारियों को साथ रखने की अनुमति दी जाएगी।

जो उद्यमी अमेरिका जाना चाहता है। उसे अपना स्टार्टअप प्लान भेजना पड़ेगा। भारतीय स्टार्टअप की जिम्मेदारी होगी। वह स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा। अमेरिका में अभी 9700 से अधिक स्टार्टअप हैं। अमेरिका में भारतीय स्टार्टअप ने 2 लाख करोड रुपए का निवेश किया है। इससे अमेरिका में 2 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अमेरिका अगले 5 साल में इसे दो गुना करना चाहता है।

अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी

अमेरिका में बेरोजगारी की दर अभी 4।10 फीसदी पर पहुंच गई है। जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। स्थानीय कारोबार और उद्यमी अमेरिका मे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके लिए अमेरिका सरकार ने भारतीयों पर दांव लगाया है। जो भारतीय उद्यमी वहां पहुंच रहे हैं। वह रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

5 साल बाद भी मिलेगा अवसर

जिस उद्यमी का कारोबार अमेरिका में बेहतर होगा। उसने स्थानीय रोजगार को बढ़ाने में बेहतर काम किया होगा। उसको अगले 5 साल के लिए रहने की अनुमति तथा ग्रीन कार्ड की पात्रता भी मिल जाएगी। अमेरिका में अभी ई 2 और ई 5 कैटेगरी में वीजा पाने के लिए 50 करोड रुपए निवेश करना पड़ता है। नई स्कीम में अब 2 करोड रुपए कर दिया है।

अमेरिका में भारतीय समुदाय मुख्य रूप से आईटी, सॉफ्टवेयर, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर में महत्ती भूमिका का निर्वाह कर रहा है।भारतीय स्टार्टअप सबसे ज्यादा सिलिकॉन वैली, सिएटल- टेक्सास में है। अक्टूबर 2024 से यह स्कीम शुरू हो जाएगी। अमेरिका की सरकार का मानना है, 60000 भारतीय स्टार्टअप के रूप में अमेरिका में निवेश करेंगे। अमेरिका के रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे।

यूपी-बिहार और झारखंड में झमाझम बारिश के आसार,महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली(ईएमएस)। मानसून लगभग पूरे देश में सक्रिय है। कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है तो कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश होने की खबरें आ रहीं हैं।हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि बारिश के बाद भी दिल्ली में उमस भरी गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 तक जा सकता है वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है।

महाराष्ट्र में बारिश से बुरा हाल है मौसम विभाग के मुताबिक आज महाराष्ट्र के पालघर, सतारा और पुणे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है। वहीं रायगढ़,सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे, और नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर और आसपास इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही चित्रकूट,मुजफ्फरनगर, कौशांबी, रामपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, और आसपास के इलाकों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। झारखंड और बिहार के कुछ जिलों में आज से लेकर 6 अगस्त तक तेज बारिश की आशंका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज इसके कुछ स्थानों पर मध्यम से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात में आज तेज बारिश तो वहीं उत्तराखंड में 7 अगस्त, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड में कल वहीं असम और मेघालय में 6 से 9 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में कहा- 2029 में चौथी बारपीएम बनेंगे मोदी

चंडीगढ़(ईएमएस)। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहे कुछ भी कर ले, 2029 लोकसभा चुनाव में एनडीए की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे।

शाह ने कहा कि विपक्ष अस्थिरता पैदा करना चाहता है। उन्हें विपक्ष में रहकर काम करने का तरीका सीखना चाहिए। विपक्ष के लोग बार-बार कहते हैं कि हमारी सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी और 2029 में फिर आएगी।

74 फीसदी घरों में स्वच्छ जल पहुंचा

चंडीगढ़ में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट न्याय सेतु के उद्घाटन और स्मार्ट सिटी मिशन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा- विपक्ष को लगता है कि थोड़ी सफलता से वे चुनाव जीत गए। उन्हें नहीं पता कि तीन चुनावों में कांग्रेस को जितनी सीटें मिलीं, भाजपा को इस चुनाव में उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। शाह ने आगे ये भी कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से स्मार्ट सिटी पर फोकस रहा है और चंडीगढ़ इस सूची में पहले स्थान पर है। अब तक एक लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। देश के 74 फीसदी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का मिशन पूरा हो चुका है। पानी से होने वाली बीमारियों में काफी कमी आई है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले देश के हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा। न्याय सेतु परियोजना के महत्व पर कहा- इस क्षेत्र के लोगों के लिए 24/7 फिल्टर-साफ पानी की आपूर्ति की जाएगी। यह परियोजना करीब 125 एकड़ में फैली हुई है।

गैंगरेप के सभी आरोपी कोर्ट से हुए बरी-पीड़िता बयान से मुकरी, मेडिकल में भी पुष्टि नहीं

लखनऊ,(ईएमएस)। यूपी की सहारनपुर कोर्ट ने गैंगरेप के आरोप में बंद तीन लोगों को बरी कर दिया है। यह तीनों बेकसूर होने के बाद भी छह माह तक जेल में रहे। कोर्ट में नाबालिग की ओर से मुकदमा दर्ज कराने वाले चाचा के लड़के और पीड़िता भी बयान से पलट गई और मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इसलिए कोर्ट ने तीनों को बइज्जत बरी कर दिया।

पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया, वजह नहीं बता सकती। पीड़िता ने पुलिस के दबाव और कहने पर झूठा बयान दिया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर सत्र न्यायाधीश पिंकू कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता का चचेरा भाई जिसने मुकदमा दर्ज कराया था। वह भी अपने बयानों से पलट गया। उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। तीनों 25-25 हजार रुपए व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करें। उनके द्वारा धारा-437-क भारतीय दंड संहिता के अनुपालन में दाखिल किए गए प्रतिभू 6 माह की समयावधि तक प्रभावी रहेंगे।

बचाव पक्ष के वकील ने बताया- कोर्ट में पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। पहले बालिग-नाबालिग को लेकर बहस चलती रही। उसके बाद मेडिकल परीक्षण में नाबालिग की उम्र 17 साल निकली। जबकि मुकदमे में पीड़िता की उम्र 12 साल बताई गई थी, लेकिन वादी ने मुकदमा दर्ज करने में 13 साल उम्र बताई गई। वहीं पीड़िता और वादी के बयानों में विरोधाभास मिला। पीड़िता ने बयान में पहले गय्यूर के मकान ले जाने और फिर जंगल में छोड़ने की बात कहीं गई। बाद में पीड़िता बयान से ही पलट गई। जबकि वादी ने ऐसी किसी भी घटना को लेकर इनकार कर दिया। साथ ही कोरे कागज पर अंगूठा लगाने की बात कही।

मशहूर भरतनाटयम डांसर यामिनी का निधन

मुंबई(ईएमएस)। भरतनाटयम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन से डांसिंग वर्ल्ड का बड़ी क्षति हुई है। उनके फैंस और करीबी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति के निधन की खबर उनकी मैनेजर और सेक्रेटरी गणेश ने दी है। यामिनी ने शनिवार 3 अगस्त को अपोलो हॉस्पिटल में जीवन की अंतिम सांस ली। वह 84 साल की थीं। मैनेजर के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वह लंबे समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रही थीं। वह पिछले 7 महीने से आईसीयू में भर्ती थीं। बता दें, यामिनी कृष्णमूर्ति को बचपन से ही डांस में दिलचस्पी थी। उन्होंने ट्रेडिशनल डांसिंग जैसे भरतनाटयम और कुचिपुड़ी में कई अवॉर्ड अपने नाम किये थे। साल 1968 में उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण (2001) और 2016 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में वह मशाल वाहक के रूप में जानी-जाती थीं।

वायनाडः त्रासदी झेल रहे परिवारों के बंद घरों में चोरी और लूट

-सूने घरों पर चोर बोल रहे धावा, पुलिस ने बढ़ाई गश्त

वायनाड,(ईएमएस)। केरल के वायनाड में जहां एक ओर आफत बरस रही है तो वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इंसानियत को बदनाम कर रही हैं। भूस्खलन की त्रासदी झेल रहे परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं लेकिन अब उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि जिंदगी बचाने के लिए जिन घरों को उन्होंने छोड़ा वहां अब चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों ने अपने घरों में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है।

प्रभावित लोगों ने पुलिस से कहा कि वह इलाके में गश्त बढ़ाएं और चोरों को पकड़कर दंडित करें। एक पीड़ित ने मीडिया से कहा कि हम वह लोग हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपना सब कुछ खो दिया है। त्रासदी के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने अपना घर छोड़ दिया था लेकिन जब वापस लौटे, तो दरवाजे टूटे मिले। उन्होंने शिकायत की कि चोरों ने रिसॉर्ट में उनके कमरे को भी निशाना बनाया जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं और उनके कपड़े चुरा ले गए।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चूरलमाला और मुंडक्कई समेत आपदा प्रभावित इलाकों में पुलिस गश्त शुरू कर दी गई है। बिना अनुमति रात में प्रभावित इलाकों या पीड़ितों के घरों में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बचाव अभियान के नाम पर रात में पुलिस की अनुमति के बिना किसी को भी प्रभावित क्षेत्रों या घरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

बता दें वायनाड में हुए भयानक भूस्खलन के बाद प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चल रहा है। इस हादसे में मृतकों की संख्या 350 के ऊपर पहुंच गई है, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने वायनाड में 6 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत आ सकती है।

श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हराया, सीरीज में श्रीलंका की 1-0 से बढ़त

कोलंबो (ईएमएस) । श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हरा दिया है। 6 विकेट लेने वाले लेग स्पिनर जेफरी वांडरसे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने भारत के टॉप-6 बैटर्स को 50 रन के अंदर पवेलियन भेज और जीत की बड़ी वजह बने। श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

श्रीलंका ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया । श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट खोकर 240 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से 2 बार 70 रन से अधिक की पार्टनरशिप हुई जिसकी वजह से श्रीलंका का स्कोर 240 तक पहुंचा। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए।

भारत से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 97 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। रोहित शर्मा ने 64 रन बनाए। यहां से लेग स्पिनर जेफरी वांडरसे ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान चरिथ असलंका ने आखिरी 3 विकेट लिए और भारत 42.2 ओवर में 208 पर सिमट गया।

क्या 12 साल की बच्ची पर भरोसा नहीं? अयोध्या रेप केस में अखिलेश यादव पर जमकर बरसी भाजपा

लखनऊ,(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला आरोपी मोईद खान, फैजाबाद-अयोध्या लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है और सपा नेता भी है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, मोईद खान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मोईद खान की तस्वीरें साझा करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। पूनावाला द्वारा साझा की गई तस्वीरों में मोईद खान को फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ बैठे देखा जा सकता है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मोईद की सपा नेताओं के साथ कई तस्वीरें हैं। सपा नेताओं ने परिवार पर केस वापस लेने का दबाव भी बनाया। अखिलेश जी बलात्कारी मोईद को बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि लड़के तो लड़के ही रहेंगे उनका सिद्धांत है।बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा, एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों (पीडीए) की बातें करती है, लेकिन अब जब एक 12 वर्षीय निसाद समुदाय की लड़की के साथ रेप हुआ और आरोपी 65 वर्षीय मोईद खान, जो फैजाबाद से समाजवादी पार्टी की कोर टीम का हिस्सा है, न केवल रेप करता है बल्कि उसका वीडियो भी बनाता है, तब अखिलेश यादव पीडीए को भूलकर मोईद खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या उन्हें 12 साल की बच्ची पर भरोसा नहीं है?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। सीएम योगी ने बीकापुर विधानसभा के विधायक डॉ. अमित चौहान के साथ आए परिजनों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विश्व बैंक ने ताजा रिपोर्ट-दुनिया में हर 3 में से 2 लोग गरीबी के जाल में

बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में चीन को 10... तो भारत को लगेंगे 75 साल

नई दिल्ली(ईएमएस)। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट टॉप पर रखा है और इसके लिए 2047 तक की डेडलाइन तय की है। वहीं इस बीच हाल ही में आई वल्र्ड बैंक की रिपोर्ट में इस लक्ष्य को पाने के बीच आने वाली चुनौतियों के बारे में जिक्र करते हुए बताया गया है कि आखिर देश कब तक ये इसे पा सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को हाई इनकम वाले देश का दर्जा पाने में अभी लंबा समय लग सकता है। रिपोर्ट की मानें तो भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के महज एक-चौथाई तक पहुंचने में ही 75 साल का समय लग सकता है। फिलहाल भारत की प्रति व्यक्ति आय 2200 डॉलर के आस-पास है, जबकि अमेरिका में ये करीब 37,000 डॉलर है।

एक ओर जहां अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के एक चौथाई हिस्से तक पहुंचने में भारत को 75 साल का समय लग सकता है, तो वहीं वल्र्ड बैंक के मुताबिक, इंडोनेशिया को भी ये टारगेट हासिल करने में सात दशक का समय लग सकता है। इस बीच अगर बात ड्रैगन की करें, तो चीन भारत और इंडोनेशिया से बहुत पहले इस आंकड़े को छूने में कामयाब हो सकता है। विश्व बैंक का कहना है कि चीन इस टारगेट को 10 साल में ही पा सकता है। वल्र्ड बैंक की इस ताजा रिपोर्ट में साल 2023 के अंत में दुनिया के 108 देशों को मिडिल इनकम ग्रुप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनकी प्रति व्यक्ति सालाना जीडीपी 1,136 यूएस डॉलर से लेकर 13,845 डॉलर के बीच थी। इन देशों में 6 अरब लोग रहते हैं, जो वैश्विक आबादी का 75 फीसदी है। वल्र्ड बैंक के मुताबिक, दुनिया में प्रत्येक तीन में से दो लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

भारत के सामने चुनौतियां

विश्न बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बीते 50 सालों के अनुभव के आधार पर पाया है कि जैसे-जैसे देश अमीर होते जाते हैं, वे आम तौर पर सालाना स् की प्रति व्यक्ति जीडीपी के लगभग 10 फीसदी के जाल में फंस जाते हैं। ये 10 फीसदी की रकम फिलहाल करीब 8,000 डॉलर के बराबर हो जाती है। भारत की चुनौतियों के बारे में बताते हुए इसमें कहा गया है कि तेजी से बूढ़ी होती आबादी, बढ़ता कर्ज, भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनाव के अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक रूप से आगे बढऩे में पेश आ रही कठिनाई इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है।

जाल से निकलने का उपाय

अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने इस जाल से निकलने के लिए क्या उपाय जरूरी हैं, इसके बारे में भी बताया है। इसमें कहा गया है कि कई मिडिल इनकम ग्रुप वाले देश अभी भी पिछली सदी की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रमुख रूप से निवेश को बढ़ाने पर जोर दिए जाने की नीतियों पर निर्भर हैं। जो कि बिल्कुल कार को पहले गियर में चलाने और उसे तेज चलाने की कोशिश करने जैसा ही है। वल्र्ड बैंक ने कहा है कि इन देशों को मिडिल इनकम ट्रैप से निकलने के लिए थ्री-आई पर फोकस करना चाहिए। ये तीन आई इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और नई तकनीक में इन्फ्यूजन हैं।

वसुंधरा राजे के पद, मद और कद के बयान ने बीजेपी में मचाई हलचल

-चर्चा का बाजार गर्म, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं, पांच सीटों पर होने हैं उपचुनाव

जयपुर,(ईएमएस)। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह में पद-मद और कद का जिक्र किया तो बीजेपी में हलचल मचा गई। वसुंधरा राजे ने समारोह में इशारों ही इशारों में एक तीर से कई निशाने किए। राजे के बयान के बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन राजे के बयान से माना जा रहा है कि बीजेपी में सबकुछ ठीक नहीं है। अभी भी अंदरखाने में 'साइलेंट जंग' चल रही है। यह जंग 5 विधानसभा सीट के लिए होने वाले उप चुनाव में अपना असर दिखा सकती है।

जयपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी चर्चाओं में रही। इस समारोह में राजे ने पद-मद और कद का जिक्र कर बिना नाम लिए कई नेताओं पर हमला बोला। राजे की मौजूदगी और उनका भाषण राजनीति के गलियारों में चर्चा बना गया है। राजे ने मदन राठौड़ की तारीफ करते हुए कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व ने सेवाभावी, सरल और ईमानदार नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उन्हें राठौड़ पर विश्वास है। इसके साथ ही राजे ने कहा कि आपको सबको साथ लेकर चलना है लेकिन यह सबसे मुश्किल काम है।

वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति के सामने तीन चीजें आती हैं। पद, मद और कद। पद और मद स्थाई नहीं होते लेकिन कद स्थाई होता है। राजनीति में यदि किसी को पद का मद आ जाए तो फिर उसका कद कम हो जाता है। आजकल लोगों को पद का मद आ ही जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी नजर में सबसे बड़ा पद है जनता की चाहत। इस दौरान राजे की दर्द भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम है उतार-चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। बहरहाल मदन राठौड़ के पदभार संभालने के बाद उनकी पहली परीक्षा आने वाले विधानसभा उपचुनाव हैं। वह अंदरखाने चल रही जंग को खत्म कर पाएंगे या फिर जुबानी तीर यूं ही चलते रहेंगे।

बांग्लादेश में हिंसा, 32 लोगों की मौत

देशभर में लगाया गया कफ्र्यू

ढाका।(ईएमएस)। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रविवार को बांग्लादेश में भडक़ी हिंसा में 32 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यहां छात्र प्रदर्शनकारी पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की बीच भिड़ंत हुआ थी।

प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कफ्र्यू की घोषणा की, पिछले महीने शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहली बार सरकार ने ये कदम उठाया है।

अफ्रीका में भारतीय को बनाया बंधक, मांग पूरी नहीं होने पर छह मंजिला से फेंका, मौत

अजमेर,(ईएमएस)। अफ्रीका में एक भारतीय युवक को कैमरून में बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। हत्यारों ने दो करोड़ रुपए की मांग की थी। मांग पूरी नहीं करने पर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक का शव इस शर्त पर परिजनों को सौंपा कि इस मामले में पुलिस में मामला दर्

जन हितैषी

न्यायपालिका के विश्वसनीयता की कलई खोली स्वयं मुख्य न्यायाधिपति ने

भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय न्याय व्यवस्था की कलई स्वयं खोलकर रख दी है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने तथा स्पेशल लोक अदालत आयोजन के समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में कहा, कि लोग न्याय प्रक्रिया से तंग आ जाते हैं। वह किसी तरह से सेटलमेंट करके न्याय प्रक्रिया से छुटकारा चाहते हैं। भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली दंडित करने जैसी है। उन्होंने स्वीकार किया, कि यह सभी जजों के लिए चिंता का विषय है। मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा- हम बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। यह बात वह इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया को लेकर आमजनता के बीच यह धारणा बनती चली जा रही है कि न्यायालय में केवल सक्षम लोगों को ही न्याय मिल सकता है। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए न्याय के नाम पर अन्याय ही किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की साख में तेजी के साथ गिरावट आई है। एक जमाना था जब न्यायाधीशों को लोग भगवान के रूप में देखते थे। न्यायालय से जो न्याय मिलता था, उसमें भले विलंब होता था लेकिन न्याय तो मिलता था। पिछले कुछ वर्षों में न्याय मिलना बंद हो गया है। न्यायालय जनता के लिए नहीं अब सरकारों के लिए काम कर रही हैं। यह स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तर्ज पर शक्तियों का बंटवारा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में किया था। तीनों के ऊपर एक-दूसरे का अंकुश था। न्यायपालिका को संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं। वह विधायिका और कार्यपालिका के किसी भी कार्य की समीक्षा कर सकती है। किसी भी संवैधानिक संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की और संविधान की रक्षा करने का दायित्व संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। न्यायपालिका में जो प्रकरण विवाद के रूप में लंबित हैं, 70 फ़ीसदी मामलों में शासन-प्रशासन और सरकार प्रतिवादी है। सरकार कानून बनाती है, लेकिन उन कानूनो का मनमाने ढंग से उपयोग करती है। सत्ता और प्रशासन में बैठे हुए लोग नियम और कानून की गलत व्याख्या करते हुए आम नागरिकों पर कार्यवाही कर देते हैं। जब न्याय के लिए वह न्यायालय में जाता है तो न्यायालयों में सुनवाई कई वर्षों तक नहीं हो पाती है। प्रशासन और शासन अपना जवाब ही प्रस्तुत नहीं करता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का यह खेल पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा हो गया है। आरोप लगते हैं कि ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीश सरकार के प्रति सहानुभूति रखते हुए मामलों की सुनवाई करते हुए नजर आते हैं। अब तो सरकार के खिलाफ निर्णय देने की स्थिति में न्यायपालिका के जज दूर-दूर तक हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसी न्यायपालिका को लेकर यदि आम आदमी इस न्याय प्रक्रिया से भागकर सत्ता में बैठे लोगों और गुंडे बदमाशों के पास जाकर न्याय पाने की कोशिश कर रहा है। यदि वहां से भी न्याय नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में अब खुद न्याय पाने के लिए अपराध की दुनिया में प्रवेश करने लगा है। अपराध नहीं कर पता है तो आत्महत्या तो कर ही लेता है। न्यायपालिका के 75 साल का इतिहास यदि मुख्य न्यायाधिपति देखेंगे और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए निर्णय को देखेंगे तो पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जिस तरह स्वयं संज्ञान में लेकर आम जनता को राहत प्रदान की जाती थी। संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका के इतिहास में जो कार्य किए गए हैं, उसी के कारण जजों को भगवान के रूप में जनता देखती थी। जनता के मन में विश्वास था सरकार प्रशासन पुलिस और सक्षम लोग यदि उसके साथ अन्याय करेंगे तो उसे न्यायालय से न्याय मिलेगा। यदि पिछले 5 साल के न्यायपालिका के कार्यकाल को मुख्य न्यायाधिपति देखें तो उन्हें खुद यह महसूस होगा कि वर्तमान की जो न्यायपालिका है वह सत्ता से डरी हुई है। न्यायपालिका का एक दौर वह भी था जिसमें न्यायपालिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को गवाही देने के लिए कोर्ट में बुला लिया। सुनवाई के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री का चुनाव भी अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय में अब यदि वादी और प्रतिवादी में से कोई पक्षकार शासन और प्रशासन का है तो ऐसे मामलों में न्यायपालिका से कोई निर्णय नहीं आता है। सरकार और प्रशासन के सामने तो न्यायपालिका ने घुटने ही टेक दिए हैं। इस तरह के मामलों में तारीख पर तारीख ही मिलती है। वर्तमान न्यायपालिका शायद अखबार भी नहीं पढती है, इसलि जनता को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं यह न्यायपालिका के संज्ञान में नहीं आ रहा है। न्यायपालिका सरकार के ऊपर इतनी अधिक आश्रित होकर रह गई है, कि सरकार जो भी निर्णय लागू करती है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका की सहायता लेकर मोहर लगवा लेती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को लेकर जो आम धारणा बन रही है वह अच्छी नहीं है। हाल ही में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए बहुत सारी याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थीं। कई याचिकाये तो 5 से 6 वर्ष पुरानी हो गई हैं। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ। 70 से अधिक परीक्षाओं के परचे लीक हुए। इस समस्या से करोड़ों युवक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे। उनके परिवारजनों की संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 10 करोड़ लोगों के बीच में न्यायपालिका को लेकर जो अविश्वास बना है यदि इसका एहसास न्यायपालिका को हो जाए तो शायद न्यायपालिका अपने आप में सुधार कर ले। भारत की संस्कृति में राजा और न्यायाधीश को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। राजा के ऊपर अंकुश रखने का काम हमेशा से भारत में न्यायाधीश ही करता रहा है। इसलिए भारत के लोगों में न्यायाधीश का दर्जा भगवान की तरह होता था, लेकिन जिस तरह का आचरण न्यायपालिका के जज इस समय कर रहे हैं। उससे उनका लोक और परलोक बन रहा है या बिगड़ रहा है यह तो न्यायाधीशों को ही सोचना होगा। सनातन परंपरा में या सभी धर्म में कर्म का फल जन्म-जन्मांतर में भोगना पड़ता है। न्यायाधीश के पद पर बैठे होने के बाद भी यदि वह अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति में कर्म का फल समय आने पर स्वयं भोगना पड़ेगा। कर्म फल को बांटा नहीं जा सकता है। भगवान को भी अपने कर्म फल भोगने के लिए मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है, यह न्यायाधीशों को भी समझना होगा।

सावन में 'शोर' नहीं, 'सोर' चाहिए!

(व्यंग्य)

सावन का महीना तो हर साल की तरह आ गया है मगर इस बार उससे जुड़े सारे उपकरण पंद्रह लाख का जुमला बनकर रह गए हैं। पवन है कि शोर करने से बाज नहीं आ रही है। शोर को 'सोर' में बदलने की सारी कोशिशें भी ढाक के तीन पात साबित हो रही हैं। बैरी बलमवा बिदेसवा तो पहले भी जाते रहे हैं और सावन में भी गए हैं, लेकिन काली से लेकर मतवाली तक कोई भी घटा उनके प्यार का संदेसवा देश में नहीं फैला सकी है। कोई बलमवा को ही प्यार के संदेश का बैरी बता रहा है तो कोई घटा में ही कालेपन की कमी बता रहा है और किसी को घटा के मतवालेपन में ही कमी नज़र आ रही है। नैया डगमगाने लगी है और खिवैया मौजों का इशारा समझने को तैयार नहीं हैं।

मेरे मुहल्ले में सामने मोड़ पर एक शिव मंदिर है जहाँ दोनों वक्त तीन चार घंटे भजन चल रहे हैं। मैं 'सावन में झूले पड़े' टाइप के गाने के दौर का बंदा हूँ इसलिए दिनोदिन सिकुड़ती जा रही हरियाली मुझे सावन जैसा कुछ एहसास होने नहीं देती। आज पेड़ों की डालियों पर बँधने वाले झूलों का नहीं बल्कि 'मेरी गो राउंड' टाइप के झूलों का दौर है जो किसी सावन के मोहताज नहीं हैं। । मगर फिर भी भजनों का यह कार्यक्रम पूरे माह जारी रहकर मुझे सावन के होने का जबरन एहसास दिलाने पर तुला रहता है। पुजारी जी और तमाम भक्तों का यह दृढ़ विश्वास है कि स्वयं तांडव करने व डमरू बजाने वाले भोले बाबा को अगर डमरू की ध्वनि से कम डेसिबल की ध्वनि में भजन सुनाए गए तो उन तक बात नहीं पहुँच सकेगी। हे भोलेनाथ! अगर तुम सृष्टि के संहारक हो तो हम भी ध्वनि के विस्तारक हैं। इसलिए अपने 'मन की बात' तुम तक पहुँचाने के लिए हम ध्वनि के विस्तारक को हृदय विदारक बनाने में कोई कसर बाकी क्यों छोड़ें?

सावन मास है शिव की उपासना का। शिव यानी कल्याण, शिव यानी तांडव, और शिव यानी संहार भी। और शिव से हमने क्या लिया? तांडव नृत्य में से सिर्फ़ तांडव, त्रिशूल से सिर्फ़ शूल चुभाने की 'कला' ले ली है। और कुछ लोग कल्याण का मतलब सिर्फ आत्मकल्याण समझ बैठे हैं इसलिए नंदियों का सारा चारा भी हड़प लिया है। गीत में सावन महीने में पवन की जिस ध्वनि का संकेत है वह सृजन व रागात्मकता का संदेश देती है। यह अर्थ सिर्फ देशज शब्द 'सोर' से ही ध्वनित होता है जहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जबकि 'शोर' के अर्थ में हिंसा व विध्वंस दोनों निहित हैं।

लोग धर्मस्थलों व केसर की क्यारियों में सिर्फ़ सावन में ही नहीं बल्कि बारहों महीने पवन का 'सोर' सुनना चाहते हैं मगर कुछ सिरफिरों की वज़ह से देश आज 'शोर' में डूबा है। (लेखक - ओम वर्मा/ईएमएस)

गैर-सरकारी संगठन में खत्म होते उद्देश्य

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को आमतौर पर गैर-लाभकारी संगठन भी कहा जाता है। ये संगठन आम तौर पर सामाजिक कल्याण, सामाजिक विकास और अन्य धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं।भारत में, इस तरह के संगठन को ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। ध्यान रखें कि ये एक जैसे नहीं हैं। संगठन की स्थापना के माध्यम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके आधार पर उनके अलग-अलग उद्देश्य और उपयोग होते हैं। इस ट्रस्ट में वैज्ञानिक संस्थान भी स्थापित किया जा सकता है। हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद मुम्बई का गठन अनुसन्धान केन्द्र में कार्यरत कुछ वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के सामूहिक प्रयास से पूर्व सन् 1968 में हुआ था। इसका गठन राष्ट्रभाषा प्रेम, जनसामान्य तक वैज्ञानिक साहित्य को पहुंचाने, वैज्ञानिक साहित्य की रचना तथा प्रसार के काम को सुसंगठित रूप में चलाने के उद्देश्य से हुआ था।' परिषद की गतिविधियों में सबसे मुख्य एवं स्थाई गतिविधि त्रैमासिक पत्रिका वैज्ञानिक का अनवरत प्रकाशन रही है। जो आज भी चल रही है हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद, मुंबई का उद्देश्य विज्ञान को हिंदी में पहुंचाने का कार्य हिंदी में रूचि रखने वाले सदस्यों के आम सभा में कार्यकारिणी की चुनाव में चयनित लोगों द्वारा संपन्न किया जाता था पहले आम सहमति से परिषद की कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता था बाद में इसमें लोगों की रूचि बढ़ि और एक पद के लिए उससे ज्यादा उम्मीदवार हो गए और चुनाव का पहला क्रम 2016 में 2016-18 हेतु आम सभा में नियमानुसार चुनाव हुआ और सभी ने कमिटी के गठन में सहयोग दिया और परिषद अपने रफ़्तार से चल पड़ी और पुनः इसी क्रम में 2018 में 2018-20 हेतु चुनाव आमसभा में हुई और पुनः कुछ नए पुराने लोगों ने मिलकर काम किया जब 2020 में कोविड का प्रकोप आया तो चुनाव को टाला गया क्योंकि प्रशासन की अनुमति ही नहीं मिली थी लेकिन चुनाव का जोड़ इस तरह पकड़ा की कोरोना की लहर 2021 में थमी की सेमिनार को रद्द करना पड़ा और इसी क्रम में सेमिनार के खर्चा को लेकर आपसी विवाद इस तरह बढ़ा कि आनन फानन में 28मार्च 21 को सचिव ने एक ऑनलाइन आम सभा बुलाकर चंद लोगों द्वारा मुद्दे को दबाकर एक चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया गया लेकिन वो सर्वमान्य नहीं था क्योंकि ऑनलाइन में लोगों की संख्या बहुत ही कम थी जब इलेक्शन को 14 अगस्त 21 को जबरदस्ती कराया गया तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि जो अध्यक्ष का पद होता है वो एक गरिमामयी पद होता है और उस पद के लिए दो लोगों ने नामांकन किया जिसमें एक उम्मीदवार अस्पताल में भर्ती था और बाई पास सर्जरी होने वाला था इसका लाभ दूसरे उमीदवार ने उठाया और सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए मनमानी और गलत तरीके से चुनाव में जीत की घोषणा चुनाव अधिकारी ने की, इतना भी समझते नहीं है कि मानवता को मार कर इलेक्शन जीत कर भी दूसरों का दिल को नहीं जीत पाएं ऐसे पद भी मिल जाए तो मैं इंसान नहीं हैवान हो जाऊंगा अतः जो समझदार थे वो एक एक कर किनारा कर लिया और अब भी लगता है कि मैं अध्यक्ष हूँ ऐ भूल है इंसान इंसान के काम ना आ सके तो जीने का मतलब ही क्या? यदि आप सही में ईमानदार और सच्चे हैं, तो इसका अभिमान न करें। कभी-कभी पद के लालच में लोग अव्यावहारिक होकर कठोर बन जाते हैं और इन्सानियत की धुन में अपनी दया, करुणा एवं सहयोग की भावना को खो बैठते हैं तथा दूसरों पर संदेह करने, दूसरों से घृणा करने लगते हैं। एनजीओ आज ठीक नहीं है इन्सानियत होने के अतिरिक्त उचित सहायता-सहयोग देने के लिए सदैव प्रस्तुत रहने की भावना होना मनुष्य को स्वस्थ और संतुलित रखता है, मानव को मानव बनाये रखता है। कभी-कभी लालच की धुन मनुष्य को वहमी बना देती है। व्यावहारिता और यथार्थ का धरातल कभी न छोड़ें। गैर-सरकारी संगठन का उद्देश्य मानव हित होता है तथा सीमा से परे जाने पर सिद्धान्त अमानवीय हो जाते हैं।यदि आप ईमानदार है, तो दूसरों से प्रशंसा की आशा कदापि न करें, क्योंकि इस संसार में बेईमान अथवा ईर्ष्यालु लोग प्रायः बिना संकोच ईमानदार आदमी पर झूठे आरोप लगाया करते हैं। दूसरों के मुख पर कालिमा पोतने से पूर्व ईर्ष्यालु के हाथ काले हो जाते हैं। दूसरों को फँसाने के लिए बिछाया हुआ जाल अवश्य एक दिन जाल बिछानेवाले को ही फँसा देता है। दूसरों के लिए गड्ढ़ा खोदनेवाला स्वयं ही उसमें गिर पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। यदि हमारा अन्तःकरण स्वच्छ है, आत्मा प्रबल है और ईश्वर के दैवी न्याय एंव सामर्थ्य पर भरोसा सच्चा है, तो अकारण द्वेषी हमारी हानि नहीं कर सकता है, अपना ही सब कुछ खो बैठेगा। लोभ यानी लालच ऐसी बुराई है, जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। किसी व्यक्ति के प्रति मन में घृणा और क्रोध नहीं बसा लेना चाहिए तथा घृणा और क्रोध से प्रेरित होने के बजाय न्याय एवं सत्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम समाज-हित में, न्याय के समर्थन में, संघर्ष करें तथा दुष्ट को दण्ड दें, किंतु घृणा अथवा बदले की भावना से किसी को नष्ट करने के लिए उतारु न हो जाएँ।संघर्ष में अपराध-वृत्तिवाले (क्रिमिनल) दुष्टों का सहारा लेकर विजय पाने पर भी आपको एक दिन पराजय का मुँह देखना पड़ेगा; क्योंकि वे अंत में आपको भी शिकार बनाये बिना न रह सकेंगे। ईश्वर जिसे आयु और आजीविका प्रदान करता है, हमें मूर्खतावश उसके साथ एक क्षणभर में ही उकताहट हो जाती है। जिसे प्रभु जीवन का अवसर दे रहा है, हमें उससे घृणा करने का अधिकार नहीं है। विरोध एवं संघर्ष करते हुए भी हम इंसानिय न खो बैठे तथा संघर्ष एवं विरोध का दायरा सीमित ही रखें।धीरे-धीरे जब मनुष्य विचार-क्षेत्र में ऊँचे स्तर पर आ जाता है, तब वह जीवन में अधिक उदात्त होकर तथा अधिक ऊँची वस्तुओं में रुचि लेकर तुच्छ प्रकार के संघर्ष करना छोड़ देता है तथा अधिक उपयोगी दिशा में संघर्ष करना प्रारंभ कर देता है। यह पलायान नहीं, बुद्धिमता होती है, जीवन में स्वस्थ मोड़ होता है। इसे पलायन कहना भूल होती है। पलायन के मूल में भय होता है तथा मोड़ का कारण होता है-मन का ऊँचे धरातल पर पहुँचना। सन्त-वृत्ति अपनाने पर तथा आध्यात्मिक रुचि ग्रहण कर लेने पर, मनुष्य धन अथवा पद आदि के लिए लौकिक संघर्ष से अधिक-से-अधिक संभव सीमा तक दूर हटकर स्वाध्याय, ज्ञानार्जन, ध्यान के अभ्यास, प्रार्थना, परोपकार, सेवाकार्य आदि में जुट सकता है। यह रुचि परिष्कार कहलाता है। अरविंद घोष सहसा राजनीति से हटकर अध्यात्म में लग गये थे।

अपनी रुचियों को खोजकर उन्हें उचित दिशा देने से विशेष सुख मिलता है। यदि आपमें कलाकार, चित्रकार, वैज्ञानिक, विचारक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता छिपा पड़ा हो, तो उसे जगायें। यश की इच्छा छोड़कर अपने व्यक्तित्व की गहरी माँगों को तन्मयता से पूरा करके उसका विकास करना मानो ईश्वर की योजना को पूरा करना है तथा प्रगाढ़ सुख की ओर बढ़ना है।ईमानदारी का फल सदा मीठा ही होता है। प्रभु आपको किसी अन्य रूप में(स्वास्थ्य, यश, पुत्रादि की उन्नति) पुरस्कार देगा। वास्तव में सुख मन की एक आन्तरिक अवस्था है, जो बाह्य पदार्थों पर निर्भर नहीं है तथा चरित्रवान् व्यक्ति को वह सहज ही प्राप्त हो जाती है। आन्तरिक सुख ही चरित्र का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार होता है। जिनके पास धन और ऐश्वर्य है, किंतु आन्तरिक सुख नहीं है, वे अभागे हैं। भीतर का धन ही सच्चा धन है। (लेखक-संजय गोस्वामी/ईएमएस)

आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों यानी एससी-एसटी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक, न्यायसंगत, समानतापूर्ण बनाने का सराहनीय कार्य किया है। न्यायालय के इस तरह के फैसले मिसाल ही नहीं, मशाल बन कर सामने आ रहे हैं, जिससे राष्ट्र की विसंगतियों एवं विडम्बनाओं से मुक्ति की दिशाएं उद्घाटित हो रही है। यह फैसला कई बिल्कुल अलग-अलग वजहों से अहम माना जा रहा है। क्योंकि बड़ा सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी-एसटी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी-एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसीलिए हुआ है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई, जैसी ओबीसी आरक्षण में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी समुदाय एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह वस्तुस्थिति नहीं थी, इस विसंगति को सुधार कर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायसंगत उपक्रम किया है। अब राज्यों एवं केन्द्र सरकार को बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। इस ताजे फैसले के बाद अनेक राज्यों में जातिगत गणना की होड़ शुरु हो सकती है एवं राजनीति दलों में आरक्षण का मुद्दा नये आक्रामक रूप में उभर सकता है। लेकिन एक आदर्श समता, समानता एवं संतुलनमूलक समाज-व्यवस्था को निर्मित करने की दिशा में कोर्ट का यह फैसला अहम है।

संविधान पीठ के अनुसार, आरक्षण का मुख्य मकसद आर्थिक और सामाजिक समानता लाना है, पर इसके लिए शहर और गांव की सामाजिक हकीकत में अंतर के साथ आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। एससी समुदाय में भी दो बड़े वर्ग है, जिनमें गहरा फासला है। बड़े अफसरों और बड़े वकीलों के बच्चों की तुलना में मैला ढोने वाले बच्चों से करना कैसे न्यायसंगत हो सकता है? इसलिए पीछे रह गई जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए ओबीसी की तर्ज पर एससी में भी कोटे के भीतर कोटे को न्यायाधीशों ने सांविधानिक माना है। आज के समय में इस फैसले की जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि देश में 140 करोड़ जनसंख्या की सामाजिक स्थिति और आर्थिक हैसियत के आंकड़े स्पष्ट तौर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक आरक्षण की मांग बढ़ने से सामाजिक और राजनीतिक विद्वेष बढ़ सकता है। क्या इस फैसले से राज्यों में मनमानी बढ़ सकती है? अब नौजवानों से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे रोजगार, कोचिंग, अग्निवीर, नीट, इंटर्नशिप, नकल और शिक्षा पर बहस के बीच इस फैसले से क्रीमीलेयर का मुद्दा फिर गरमा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका भी है, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी-एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। वैसे भी अब तक देश में आरक्षण वोट बैंक को सुदृढ़ बनाने का हथियार बना रहा है और राजनीतिक दल इसका अनुचित लाभ उठाते हुए अपेक्षित समुदायों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचने दिया।

सुप्रीम कोर्ट के नये फैसले के बाद स्थितियां उग्र एवं आक्रामक होने के साथ प्रभावी भी होगी। इसलिये अब आरक्षण का कई पहलुओं से मूल्यांकन जरूरी हो गया है। वैसे फैसले में साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण स्पष्ट और भरोसेमंद डेटा के ही आधार पर ही किया जा सकता है। देखा जाए तो इस शर्त के जरिए फैसले का संकीर्ण एवं स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की संभावित कोशिशों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला, ईडब्ल्यूएस जैसी सभी वर्गों के आरक्षण को जोड़ा जाए, तो 99 फीसदी आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाती है। चारों राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर देखें, तो इस फैसले के बाद आरक्षण की राजनीति के साथ अदालतों में मुकदमेबाजी भी बढ़ सकती है, जिसका समाधान सूझबूझ एवं लोकतांत्रिक तरीके से करना होगा। अनुच्छेद-19 के तहत नागरिकों को पूरे देश में व्यवसाय और रोजगार का अधिकार है, इसलिए आरक्षण के माध्यम से न्याय और समानता स्थापित करने के लिए जातियों के व्यापक वर्गीकरण की राष्ट्रीय नीति को न्यायिक मान्यता देनी पडेगी।

आरक्षण के बावजूद अपेक्षित लोगों को इसका लाभ न मिलना संवैधानिक एवं राजनीतिक विसंगति का प्रमाण है। ताजे फैसले के बाद राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में भी आरक्षण के लिए अलग-अलग श्रेणियां बना सकती हैं। इस फैसले के बाद इन वर्गों में हाशिए पर पड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिलने की उम्मीद जगी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह बात भी लगातार उठाई जा रही थी कि समुचित अवसर नहीं मिलने के कारण आरक्षित एससी-एसटी वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन से उबर नहीं पा रही हैं। आरक्षण के बावजूद भूमिहीन एवं निर्धन लोगों की स्थिति आज भी दयनीय एवं असंतुलित है। क्योंकि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति गांव में रहने वाले भूमिहीन-निर्धन-अभावग्रस्त लोगों के बच्चों जैसी है। सच यही है कि आरक्षण की व्यवस्था का फायदा भी एससी/एसटी श्रेणी के तहत आने वाली सभी जातियां समान रूप से नहीं उठा सकीं। ताजा फैसला इस सचाई को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों के लिए यह गुंजाइश बनाता है कि वे इस व्यवस्था का फायदा उन तबकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें जिन तक यह ठीक से नहीं पहुंचा है।

हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करते समय भी इसी बात की जरूरत महसूस की गई थी कि आरक्षण व्यवस्था से समाज के वंचित और उपेक्षित वर्ग-समुदाय को समाज की मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा। ऐसा हुआ भी। पर इस तरह की आवाजें भी लगातार उठने लगी हैं कि एससी-एसटी वर्ग में कुछ लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है और कुछ तक आरक्षण व्यवस्था का अंश तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर इन आरक्षित वर्गों में ही विद्रोह के भाव भी समय-समय पर देखने को मिलते रहे हैं। अच्छा होगा कि एससी-एसटी आरक्षण का उपवर्गीकरण करने के साथ ही उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। आरक्षित वर्गों में जो भी अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, वंचित-निर्धन लोगों के साथ किया जाने वाला अन्याय भी है। आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाला पात्र है या नहीं? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी समुदाय में आरक्षण के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जरूरत जता दी है, तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े। कुल मिलाकर, ताजा फैसला न सिर्फ नीति-निर्माण के स्तर पर महत्वपूर्ण दखल है बल्कि आरक्षण जैसे मसले पर भविष्य के लिए दिशासूचक का भी काम कर सकता है।(लेखक- ललित गर्ग/ ईएमएस)

शब्द पहेली - 8089

बाएँ से दाएँ

1. तन,शरीर-3
3. चकोर,चंद्रप्रेमी पक्षी-3
6. झगड़ा,द्वेष-3
7. मोटा आटा-2
8. खिंचाव,स्वर विस्तार-2
9. असली,शुद्ध-3
10. यंत्रशाला-4
12. कार्यविधि-3
14. चिंगारी-3
16. एक कंद जिसे सुखा कर सौंठ बनाई जाती है-4
18. दूल्हे की पगड़ी-3
20. सम्मान-2
21. प्राण,जीवन तत्व-2
22. कुशल,होनहार-3
24. राशिचक्र की एक राशि-3
25. प्रेमी,साजन- 3

ऊपर से नीचे

2. अवलोकन,दरस-3
3. चलने का ढंग-2
4. तलघर-4
5. इस पर रोटी सेंकते हैं-2
6. जलजला-3
7. रसीला,रस से भरपूर-4
8. बल,जोर,दम-3
10. चाचा,अंकल-2
11. शौहर,पति-3
13. 'दीवाने हुए पागल' की नायिका-2,2
14. वहम,संदेह-3
15. राजा,सम्राट-3
16. उपद्रवी,आतंकी-4
17. गिरवी रखी वस्तु-3
20. बैठने की जगह-3
21. शराब का प्याला-2
23. रांझे की प्रेमिका-2

शब्द पहेली -8088 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

विनेश सहित भारतीय पहलवान आज मुकाबले में उतरेंगे

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक में सोमवार को भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट सहित सभी सभी छह पहलवान मुकाबले में उतरेंगे। विनेश ने विश्व चैंपियनशिप में दो, राष्ट्रमंडल खेलों में तीन और एशियाई चैंपियनशिप में आठ पदक जीते हैं पर इस बार उन्हें अभ्यास का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। वह भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हुए आंदोलन में भी शामिल रही थी। ऐसे में उसकी तैयारियां प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा व वह विश्व चैंपियनशिप में भी भाग नहीं ले पायी थी।

वहीं अंतिम पंघाल ने उनके वजन वर्ग 53 किग्रा में कोटा हासिल किया था। इस कारण विनेश को इस बार 50 किग्रा वजन वर्ग में उतरना पड़ रहा है। वह गैर वरीयता प्राप्त है जिसका मतलब है कि उनकी रहा आसान नहीं रहेगी। इसका कारण है कि विनेश के इस वजन वर्ग में कई स्टार पहलवान शामिल हैं जिनमें विश्व चैंपियन युई सुसाकी, ओलंपिक पदक विजेता मारिया स्टैडनिक, पिछले ओलंपिक खेलों की कांस्य विजेता सारा हिल्डेब्रांट आदि।

लक्ष्य पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में हारे,कांस्य के लिए मुकाबला आज

पेरिस (ईएमएस)। भारत के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल लक्ष्य सेन को पेरिस ओलंपिक खेलों की पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। लक्ष्य को इस मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने 22-20, 21-14 से हराया। अब लक्ष्य सोमवार को कांस्य पदक के लिए मलेशिया के ली जी जिया से खेलेंगे। दूसरे गेम में लक्ष्य ने अच्छी शुरुआत की और वह एक समय तक 6-0 से आगे थे पर इसके बाद एक्सेलसन ने वापसी करते हुए स्कोर 4-8 कर दिया। एक्सेलसन ने इसके बाद स्कोर 13-12 कर दिया। इसके बाद दो अंक विक्टर के पक्ष में गए और स्कोर 15-12 पहुंच गया। एक्सेलसन ने इसके बाद एक के बाद एक अंक हासिल किये और 17-13 से आगे हो गए। लक्ष्य इसके बाद वापसी में असफल रहे। विक्टर ने दूसर

रिजर्व बैंक के ब्याज दर पर फैसले, वैश्विक बाजारों के रुख तय करेंगे शेयर बाजार की दिशा

- कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव तथा रुपये के रुख पर भी रहेगी बाजार की नजर

नई दिल्ली (ईएमएस)। इस सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ब्याज दर पर ?लिए गए फैसले, वृहद आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक बाजारों के रुख से शेयर बाजारों की दिशा तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। विश्लेषकों ने कहा कि बाजार भागीदारों की नजरें वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव तथा डॉलर के मुकाबले रुपये के रुख पर भी रहेगी। बाजार के विश्लेषकों ने कहा कि इसके अलावा विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण भू?मिका ?निभाएंगे। सेवा क्षेत्र के एचएसबीसी पीएमआई आंकड़ों की घोषणा सोमवार को होगी। बाजार ?विश्लेषकों ने कहा ?कि इस सप्ताह सभी की नजरें वैश्विक बाजारों पर रहेगी। लंबे समय की स्थिरता के बाद अब बाजार में कमजोरी का कुछ संकेत दिखने लगा है। इससे भारतीय बाजार की मजबूती की परख होगी, जो तरलता की बेहतर स्थिति की वजह से अभी तक जुझारू बना हुआ है। उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर आठ अगस्त को आने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण रहेगी। पहली तिमाही के नतीजों के आखिरी दौर से बाजार में कुछ शेयर विशेष गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा संस्थागत प्रवाह भी बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सप्ताह के दौरान भारती एयरटेल, बीईएमएल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, भारतीय जीवन बीमा निगम और एमआरएफ जैसी बड़ी कंपनियां अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। एक अन्य बाजार ?विश्लेषक कहते हैं ?कि आगे चलकर ऊंचे मूल्यांकन की वजह से बाजार में कुछ कमजोरी आ सकती है। इस सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक से ब्याज दरों के परिदृश्य पर कुछ संकेत मिलेगा। फिलहाल केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर यथास्थिति बरकरार रख सकता है।

कच्चे तेल के भाव गिरे, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बदलीं

- कच्चे तेल का दाम 77 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे

नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने र?विवार को पेट्रोल-डीजल के नए भाव में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव क दौर लगातार जारी है। जारी भाव के अनुसार कच्चे तेल का दाम 77 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है। वै?श्विक बाजार में र?विवार को ब्रेंट क्रूड 76.81 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड 73.52 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है भारत में फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेल कंप?नियों के मुता?बिक अलग-अलग महानगरों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमतें इस प्रकार हैं- दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर, गुरुग्राम में पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर, बेंगलुरु में पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर, चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर, हैदराबाद में पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर, जयपुर में पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर और पटना में पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर है।

एफआईपी की उड़ान डयूटी के संशोधित मानदंड लागू करने की मांग

मुंबई (ईएमएस)। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने नागर विमानन मंत्रालय को लिखे पत्र में पायलटों को होने वाली थकान पर चिंता जताते हुए संशोधित मानदंडों को तत्काल क्रियान्वित करने की जरूरत बताई है। पायलटों के समूह एफआईपी के 6,000 से अधिक सदस्य हैं। एफआईपी ने इससे पहले भी नागर विमानन मंत्रालय को संशोधित नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) पर पत्र लिखा था, क्योंकि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इसके क्रियान्वयन को टाल दिया था। उड़ान डयूटी समयसीमा से संबंधित संशोधित सीएआर पायलट की थकान पर बढ़ती चिंताओं के बीच उन्हें आराम के लिए अधिक समय देने से संबंधित है। मार्च में डीजीसीए ने इसके क्रियान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू को लिखे पत्र में एफआईपी अध्यक्ष सीएस रंधावा ने उनसे संशोधित सीएआर को जल्द से जल्द लागू करने के लिए डीजीसीए को निर्देश देने का अनुरोध किया है। पत्र में सीएआर के क्रियान्वयन को स्थगित करने के नियामक के कदम का जिक्र करते हुए कहा गया है ?कि डीजीसीए की कार्रवाई न केवल पायलट सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी कमजोर करती है। 29 जुलाई को लिखे पत्र में यह भी दावा किया गया है कि थकान के मुद्दे की गंभीरता को पहचानने में नियामक की विफलता न केवल पायलटों बल्कि हवाई यात्रा करने वाले आम लोगों की सुरक्षा से भी समझौता करने जैसा है।

अमेरिका में पढ़ाई के लिए दस्तावेजों में हेरफेर, खुली पोल

न्यूयॉर्क,(ईएमएस)। अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए अपने कागजात में हेरफेर करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय छात्र को अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुए एक समझौते के तहत भारत वापस भेज दिया जाएगा। आरोपी ने जिंदा पिता की झूठी मौत के भी बना डाले दस्तावेज और फिर अमेरिका में पुलिस ने पकड़ा तो राज से सारे पर्दे उठ गए।

जानकारी अनुसार आर्यन आनंद (19) नामक युवक ने शिक्षण सत्र 2023-2024 में पेंसिल्वेनिया के लेहाए विश्वविद्यालय में एडमीशन के लिए फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र की पिछले माह की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि आनंद ने एडमीशन और आर्थिक मदद के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की है। विश्वविद्यालय में एडमीशन और स्कॉलरशिप प्राप्त करने की गरज से उसने अपने जिंदा पिता की मौत का भी झूठा दावा किया।

इस मामले को लेकर मजिस्टेरियल डिस्ट्रिक्ट जज जॉर्डन निस्ले की अदालत में आनंद के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। यहां पर आनंद की जमानत राशि 25 हजार अमेरिकी डॉलर बताई गई क्योंकि उसे जालसाजी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इसके साथ ही बताया गया कि उसे एक से तीन माह की सजा भी सुनाई गई। अब एक समझौते के तहत आनंद को भारत वापस लौटना होगा। उसे रिहा करते हुए अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है।

एफपीआई ने जुलाई में शेयरों में किया 32,365 करोड़ का निवेश

- जून में एफपीआई ने शेयरों में 26,565 करोड़ का निवेश किया था

नई दिल्ली (ईएमएस)। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने जुलाई में भारतीय शेयर बाजारों में 32,365 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह जानकारी डिपॉजिटरी के आंकड़ों से मिली है। हालांकि, इस महीने के पहले दो कारोबारी सत्रों 1-2 अगस्त को एफपीआई ने शेयरों से 1,027 करोड़ रुपये निकाले हैं। बजट में इक्विटी निवेश पर पूंजीगत लाभ कर बढ़ने की घोषणा के बाद से एफपीआई प्रवाह में मिला-जुला रुख देखा गया है। बाजार के जानकारों ने कहा ?कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बाजारों से जुड़े घटनाक्रम अगस्त में एफपीआई की गतिविधियों का रुख तय करेंगे। अर्थव्यवस्था में सुस्ती तथा कमजोर रोजगार के आंकड़ों के बाद यह निश्चित है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जुलाई में शेयरों में 32,365 करोड़ रुपये डाले हैं। इससे पहले जून में राजनीतिक स्थिरता और बाजारों में तेज उछाल के बीच एफपीआई ने शेयरों में 26,565 करोड़ रुपये का निवेश किया था। एफपीआई ने चुनाव नतीजों को लेकर असमंजस के बीच मई में शेयरों से 25,586 करोड़ रुपये निकाले थे। मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में निरंतर वृद्धि की चिंता के बीच अप्रैल में उन्होंने शेयरों से 8,700 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की थी। उन्होंने कहा कि एफपीआई का प्रवाह बढ़ने की वजह सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान देना, उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे और सतत आर्थिक वृद्धि है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ा दिया है। वहीं चीन के वृद्धि दर के अनुमान में कमी की गई है। यह भी भारत के पक्ष में गया है।

पिछले पांच वर्षों में आईपीओ से पूंजी जुटाने में भारत शीर्ष पर, आईपीओ को लेकर प्रक्रिया सरल करने में जुटा सेबी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राथमिक बाजारों को जल्द ही और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुव्यवस्थित करने के साथ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक नया तरीका तैयार किया जा रहा है। इससे कंपनियां कम समय में पूंजी जुटाने में सक्षम होगी, इससे निजी पूंजीगत खर्च को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में तेजी का फायदा उठाते हुए विभिन्न कंपनियों ने आईपीओ, राइट निर्गम और पात्र निजी नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से इस साल अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। एक कार्यक्रम में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा, पूंजी बाजार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूंजी निर्माण की होती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वैश्विक स्तर पर भारत आईपीओ और अन्य निर्गम जारी करने की संख्या के आधार पर पहले स्थान पर है।

बुच ने कहा कि ज्यादा पूंजी जुटाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सेबी जल्द ही नई व्यवस्था करेगी। इसके तहत निर्गम दस्तावेज के लिए नियामक 'सरल' प्रारूप पेश करेगा जिसमें रिक्त स्थान को भरने जैसा आसान तरीका होगा और जटिलताओं को समझाने के लिए एक अलग भाग होगा। बुच ने घोषणा की कि सेबी पूंजी जुटाने के एक नए तरीके पर काम कर रहा है जो राइट निर्गम और क्यूआईपी को संचालित करने वाले ढांचे की तरह होगा। सेबी प्रमुख ने कहा कि बड़ी तादाद में आईपीओ आवेदनों को देखकर नियामक इसकी जांच-परख और मंजूरी में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास कर रहा है। सेबी प्रमुख बुच ने कहा कि आईपीओ दस्तावेज की मंजूरी में लगने वाला समय कम हुआ है मगर अपूर्ण दस्तावेज, आवेदनों में विसंगति या आंतरिक जांच-परख के कारण कुछ देर होती है।

कुछ आईपीओ आवेदनों में खामियों के कारण अच्छे आईपीओ को मंजूरी हासिल करने की राह में बाधा होती है। बाजार नियामक तेजी से मंजूरी के लिए आर्टिफशल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है और 80 फीसदी काम इस तकनीक के द्वारा किया जा रहा है। नियामक ने इस साल जुलाई तक 86 आईपीओ आवेदनों की जांच-परख की है। इसमें से 65 को मंजूरी दी गई और 16 को लौटा दिया गया, जबकि 4 आवेदन वापस ले लिए गए।

सेबी पूंजी जुटाने के नए तरीके पर प्रतिक्रिया लेने जल्द ही परामर्श प्रक्रिया शुरू करेगा। बुच ने कहा, 'हम राइट निर्गम और तरजीही आवंटन के लिए कॉम्बो प्रोडक्ट लाएंगे। राइट निर्गम की मौजूदा 23 दिन और तरजीही आवंटन की मौजूदा 42 दिन की समयसीमा घटाकर आधी की जाएगी। उन्होंने कहा, 'इस कदम का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को एक्सप्रेसवे की तरह तेज बनाना है ताकि पूंजी तेजी से कम खर्च पर जुटाई जा सके और इसमें निवेशकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।' प्राइस डेटाबेस के अनुसार इस साल अभी तक 40 कंपनियों ने पूंजी बाजार से 36,286 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगले हफ्ते 4 आईपीओ आने वाले हैं जिससे कुल 12,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।

प्राकृतिक खेती ने खोले समृद्धि के द्वार : गुजरात के युवक ने सब्जी की बुवाई की, तीन वर्ष में आय 700 प्रतिशत के पार

- पहले वर्ष में आय 55 हजार रुपए, तीसरे वर्ष में आय 4.4 लाख रुपए से अधिक

- इस वर्ष वर्षा के मौसम में स्ट्रॉबेरी के 25 हजार पौधे बोए, प्राकृतिक खेती कर आदिवासी युवक बना आत्मनिर्भर

अहमदाबाद (ईएमएस)'हमारा डांग, प्राकृतिक डांग' अभियान अंतर्गत दक्षिण गुजरात के वनवासी क्षेत्र डांग को वर्ष 2021 में संपूर्ण प्राकृतिक खेतीयुक्त जिला घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्राकृतिक खेती की व्यापकता बढ़ाने के लिए सघन प्रयास शुरू किए हैं और इस वर्ष केन्द्रीय बजट में भी समग्र देश में लगभग 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सघन प्रयासों से आज राज्य में प्राकृतिक खेती की व्यापकता बढ़ रही है। डांग को प्राकृतिक खेतीयुक्त जिला घोषित किए जाने के बाद यहाँ खेती से जुड़े आदिजाति युवाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिले हैं। जिला मुख्यालय आहवा तहसील के गलकुंड गाँव में रहने वाले राजूभाई साहर की साफल्य गाथा प्राकृतिक खेती की सफलता को दर्शाती है।

2 हेक्टेयर क्षेत्र में टपक सिंचाई पद्धति से खेती, 2023 में मुनाफा 3 लाख रुपए के पार

40 वर्षीय राजूभाई बुधाभाई साहर ने बागवानी विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बागवानी खेती की शुरुआत की थी। उन्होंने वर्ष 2021 में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में करेले की बुवाई कर 55 हजार रुपए की आय अर्जित की थी, जिसमें उन्हें 40 हजार रुपए का मुनाफा हुआ था। प्राकृतिक खेती में अच्छी उपज मिलने से उन्होंने विभिन्न फसलें लगाना शुरू किया और वर्ष 2023-24 में मल्चिंग तथा टपक सिंचाई पद्धति से मिर्च, करेला, टमाटर तथा ब्रोकली की बुवाई कर 4 लाख 40 हजार रुपए की आय अर्जित की। तीन वर्ष के भीतर ही उनकी आय में 700 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है।

''मैं नए प्रयोग करता हूँ, इस वर्ष मैंने स्ट्रॉबेरी के 25 हजार पौधे लगाए''

राजूभाई प्राकृतिक पद्धति से खेती के अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, ''इस पद्धति से उपज अच्छी मिल रही है। हम मौसम के अनुसार करेला, टमाटर, कटहल, धान आदि फसलें बोते हैं। ब्रोकली डांग के लोगों के बीच बहुत प्रचलित नहीं है, परंतु मैंने उसका प्रयोग किया। गत वर्ष मैंने स्ट्रॉबेरी के 7 हजार पौधे बोए थे और मुझे उसमें शत प्रतिशत मुनाफा मिला था। इस वर्ष मैंने स्ट्रॉबेरी के 25 हजार पौधे बोए हैं।''

''सरकार हमें सब्सिडी देती है''

राजूभाई ने कहा कि उनके परिवार में कुल चार भाई हैं, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। राजूभाई की संतानों में दो बड़ी बेटियाँ और एक बेटा हैं, जो इस समय पढ़ाई करते हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता के विषय में उन्होंने कहा, ''हमें बागवानी विभाग की ओर से सब्सिडी मिलती है। हमें अधिकारियों की ओर से आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहायता; दोनों मिलते हैं।'' बागवानी विभाग द्वारा कच्चे (अस्थायी) मंडप, बीज, प्लास्टिक आवरण, पैंकिंग मटीरियल्स तथा आम के पौधे के लिए सहायता दी जाती है।

प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 1,603 लाख रुपए की सहायता

राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण एवं सहायता का प्रावधान किया है। राज्य में किसानों के बीच प्राकृतिक खेती का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो रहा है और इसके फलस्वरूप किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान तीन वर्षों में प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को 1,603 लाख रुपए की सहायता दी गई है।

डोनाल्ड ट्रम्प की फाइल फिर ओपन

-16 अगस्त को होगी सुनवाई

वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिका के कोलंबिया की जिला अदालत ने कहा है कि उसने राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ मामले की सुनवाई फिर से शुरू कर दी है और इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त तय की है।

सुनवाई की बहाली जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित है, जिसने राष्ट्रपति रहते हुए अपने कार्यों के लिए अभियोजन से ट्रम्प को पूरी तरह छूट की मान्यता देने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति को केवल आधिकारिक क्षमता में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रतिरक्षा है, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें से कुछ इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ट्रंप ने पहले सभी अदालतों से उनके खिलाफ मामले खारिज करने को कहा था। फैसले के मुताबिक जैसे ही अदालत यह तय करेगी कि प्रतिरक्षा के अंतर्गत क्या आता है, तो ट्रम्प उन फैसलों के खिलाफ अपील कर सकेंगे।

बारिश से आफत के बाद अब महामारी का खतरा, सूरत में 16 की मौत

सूरत, 04

बारिश होते ही लोगों को जगह-जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन बारिश के बाद फैलने वाली गंदगी और महामारी नागरिकों को बीमारी और अक्सर मौत के कगार पर धकेल देती है. अधिकांश शहरों के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। फिर सूरत में भी महामारी ने सिर उठा लिया है.

शहर में गंदा पानी आने की शिकायतें मिल रही हैं। सूरत के पांडेसरा इलाके में पिछले एक हफ्ते से लाल रंग का बदबूदार पानी आ रहा है. स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं होने से स्थानीय लोग परेशान हैं. दूसरी ओर, पिछले कुछ दिनों से शहर में विकराल होती जा रही जल-जनित और मच्छर-जनित महामारी ने तीन और लोगों की जान ले ली है, जिनमें एक छह महीने की बच्ची भी शामिल है। शहर में बारिश का पानी कम हो गया है, लेकिन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे प्रदूषित पानी की महा मारी बढ़ने की शिकायतें आ रही हैं।

बताया गया है कि मानसून के दौरान फैली विभिन्न बीमारियों के कारण सूरत में 16 लोगों की मौत हो गई है। डायरिया, उल्टी से छह माह के बच्चे समेत अब तक तीन की मौत हो चुकी है। जिसमें पांडेसरा के रहने वाले एक बच्चे की सिविल में इलाज के दौरान मौत हो गई है. हजीरा में 26 वर्षीय व्यक्ति की बुखार से मौत हो गई, भेस्तान में 40 वर्षीय व्यक्ति की उल्टी दस्त से मौत हो गई। इस सीजन में मरने वालों की संख्या 16 बताई जा रही है। गंदे पानी और मच्छरों के पनपने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। उस समय शहरवासियों द्वारा जिम्मेदारों से शिकायत करने के बावजूद सरकार सिर्फ घोषणा करती है कि महामारी से बचने के लिए घर और फर्श साफ रखें, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाती. इस मामले में नगर पालिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

कभी न हारने वाले देश की चौतरफा घेराबंदी...लेबनान का इजराइल पर हमला...

ईरान के बमवर्षक विमान भी बमबारी के लिए तैयार

इजराइल पर हमला करेगा ईरान!

काहिरा(ईएमएस)। कभी न हारने वाला इजराइल अब चौतरफा हमले से घिर गया है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद बौखलाए ईरान की सेना इजराइल पर हमले के लिए जहां तैयार है, वहीं ईरान से पहले लेबनान ने इजराइल पर एक के बाद एक राकेटों की बौछार कर दी। हालांकि इजराइल ने लेबनान की हिजबुल्ला सेना द्वारा किए गए हमले को नाकाम कर दिया। उधर, दावा किया जा रहा है कि सोमवार को ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है।

ईरान में हमास प्रमुख की हत्या से पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल कमांडर को भी मौत के घाट उतारा था। हिजबुल कमांडर ने गत 28 जुलाई को इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स इलाके में एक फुटबाल मैदान पर राकेटी हमला किया था, जिससे 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद इजराइल ने हिजबुल्ला को हमास की तरह सबक सिखाने की कसम खाई थी। लेबनान ने अपने कमांडर की हत्या के बाद 100 से अधिक राकेट इजराइल के दक्षिणी शहरों में दागे हैं। संभवतः ईरान के बमवर्षक विमान भी इजराइल पर बमबारी कर सकते हैं। फिलिस्तीन के साथ पहले से युद्ध कर रहा इजराइल अब चौतरफा हमलों से घिर गया है। जहां लेबनान ने हमले शुरू कर दिए हैं, वहीं ईरान भी बड़े हमले की तैयार कर रहा है।

सही वक्त पर अटैक करेंगे

ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान इजराइल पर सोमवार को हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच गए हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका में मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और इजराइल की रक्षा के लिए नए फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया है कि वह इजराइल की हिफाजत जरूर करेगा।

अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया

यह मिसाइल हमला इजराइल ने कराया है। अमेरिकी सरकार ने भी इसका सपोर्ट किया है। हानिया जिस गेस्ट हाउस में रुका था, उसके बाहर से ही यह आतंकी ऑपरेशन चलाया गया। हानिया की मौत के दिन हमास के प्रवक्ता और उप-प्रमुख खलील अल हाय्या ने भी कहा था कि तेहरान में जिस घर में हानिया ठहरे हुए थे, उसे सीधे रॉकेट से निशाना बनाया गया। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हानिया को बम धमाका कर मारा गया। बम को ईरानी गेस्ट हाउस से 2 से 3 महीने पहले ही फिट कर दिया गया था। इसमें ईरानी इंटेलिजेंस अफसरों की भी मिलीभगत थी। ईरान ने इस मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है।

- इजराइल से बदला लेने का वादा किया

हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने का वादा किया था। उसने कहा कि फिलहाल इजराइली बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वे खूब रोएंगे। नसरल्लाह ने इजराइल से सभी मोर्चे पर खुली लड़ाई का ऐलान किया। उसने कहा कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। इजराइलियों को पता ही नहीं है कि इन मौतों पर हम कैसा जवाब देंगे। नसरल्लाह की धमकी के कुछ ही घंटे बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। इजराइली सेना के मुताबिक इसमें से सिर्फ 5 रॉकेट इजराइली सीमा में दाखिल हो पाए। हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं है।

पैसे नहीं हैं तो अमेरिकी दूतावास से लें, लेकिन लेबनान छोड़ दें-अमेरिकी नागरिकों को सलाह

वॉशिंगटन(ईएमएस)। इजरायल हमास युद्ध में अब कई देश कूद पड़े हैं। लेबनान से लेकर ईरान तक अब जंग की ओर बढ़ चुके हैं। इस बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को किसी भी उपलब्ध टिकट पर जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने आगे कहा, जिन अमेरिकी नागरिकों के पास अमेरिका लौटने के लिए पैसों की कमी है, वे वित्तीय सहायता के लिए दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि अमेरिकी नागरिक जो लेबनान से प्रस्थान न करने का विकल्प चुनते हैं, वे आपातकालीन स्थितियों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करें और लंबे समय तक ठहरने के लिए अपने आशियाने को तैयार रखें।

अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को दिए सलाह में कहा है कि 'कई एयरलाइनों ने उड़ानें निलंबित या रद्द कर दी हैं और कई उड़ानों की टिकटें बिक चुकी हैं। हालांकि, लेबनान छोड़ने के लिए वाणिज्यिक परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। कृपया बेरुत-राफिक हरीरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध उड़ान विकल्प देखें। हम लेबनान से प्रस्थान करने के इच्छुक लोगों को उनके लिए उपलब्ध कोई भी टिकट बुक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही वह उड़ान तुरंत प्रस्थान न करती हो या उनकी पहली पसंद के मार्ग का अनुसरण न करती हो। इजरायल के बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फौद को मारने का दावा किए जाने के कुछ घंटों बाद ही हानिया की मौत की खबर सामने आई थी। रविवार रात को उत्तरी इजरायल के बेत हिलेल इलाके में हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायल के हमलों में वहां के नागरिक घायल हुए हैं। वहीं इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए कई रॉकटों को रोक दिया। बता दें कि इससे पहले इसी तरह की ब्रिटेन के चेतावनी विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भी जारी की थी। लैमी ने कहा था कि क्षेत्र में स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। बुधवार को तेहरान में हुई हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजरायल पर जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है।

जल रहा ब्रिटेन, मुस्लिम और अवैध प्रवासियों के खिलाफ भड़की हिंसा

लंदन(ईएमएस)। उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड में चाकू से हुए हमले में तीन लड़कियों की मौत हो गई थी। इसके बाद यूके में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी प्रदर्शन की उम्मीद है। धुर दक्षिणपंथियों की ओर से प्रदर्शन तेज हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखी गई। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसक भीड़ और जलती हुई दुकानों की तस्वीरें अब पूरी दुनिया में शेयर की जा रही है। साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट-थीम वाली योग क्लास के दौरान चाकूबाजी की घटना के बाद तीन बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सभी शहरों में तनाव बढ़ गया है। इस पूरे बवाल का कारण आरोपी से जुड़ी एक खबर है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि साउथपोर्ट का हमलावर एक अप्रवासी मुस्लिम था जो अवैध रूप से ब्रिटेन में आया था। इसके बाद अप्रवासियों के खिलाफ विरोध की लहर देखी गई।

कार्डिफ में जन्मे 17 साल के एक्सल रुदाकुबाना पर हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। आम तौर बार बालिग आरोपी का ही नाम पब्लिक किया जाता है। इस सप्ताह इंग्लैंड के अलग-अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए दंगा पुलिस को स्टैंडबाय पर रखा गया है। वहीं धार्मिक नेताओं ने साउथपोर्ट की हत्या के बाद नफरत फैलाने के प्रयासों की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की संभावित चेतावनी के बीच किसी भी प्रदर्शन में शांति का आह्वान करने वालों में मुस्लिम, यहूदी, हिंदू और ईसाई धर्मगुरु शामिल थे।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस अशांति पर चर्चा करने के लिए शनिवार को अपने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सड़कों पर चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को पूरा समर्थन है। मैनचेस्टर, बेलफ़ास्ट, लिवरपूल और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर शनिवार को आए वीडियो में आप्रवासी-विरोधी प्रदर्शनकारियों की भीड़ लिवरपूल की नदी के किनारे इकट्ठा होकर नावों को रोको जैसे नारे लगाते हुए दिखे। दरअसल अफ्रीका और खाड़ी के अन्य देशों से भाग कर लोग यूरोप पहुंच रहे हैं। यह समुद्री रास्तों से नावों में बैठ कर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में अप्रवासी आए हैं।

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा विरमगाम-अहमदाबाद सेक्शन का संरक्षा निरीक्षण

अहमदाबाद (ईएमएस)पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने 04 अगस्त, 2024 को अहमदाबाद मण्डल के विरमगाम-अहमदाबाद सेक्शन का संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिश्र ने संरक्षा, इंफ्रास्ट्रदक्च रल कार्य और विरमगाम स्टेयशन पर यात्री सुविधाओं तथा स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया। महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र

गुजरात के सात जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान

अहमदाबाद,4 अगस्त

गुजरात भारी बारिशः राज्य में दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के इलाकों में जहां हल्की से भारी बारिश हो सकती है, वहीं मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक दक्षिण गुजरात और उत्तरी गुजरात के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. जिसमें आज (4 अगस्त) बनासकांठा, साबरकांठा, वलसाड और नवसारी जिलों में रेड अलर्ट और पाटन, मेहसाणा, सूरत, डांग और तापी समेत पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है.

जबकि राज्य में पिछले तीन दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक राज्य के 105 तालुका में बारिश हुई। जिसमें नवसारी के खेरगाम में 174 मिमी, वलसाड के अहवा और कपराडा में 119 मिमी, नवसारी के चिखली में 111 मिमी, वलसाड में 106 मिमी, नवसारी के वंसदा में 105 मिमी, डांग के वागड़ में 100 मिमी बारिश हुई है. वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में 230 तालुका में बारिश हुई है.

5 अगस्त का पूर्वानुमान

जहां पिछले कुछ दिनों से राज्य में हल्की से भारी बारिश हो रही है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। 5 अगस्त को नवसारी, वलसाड, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग और तापी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। जबकि मध्य और उत्तरी गुजरात में साबरकांठा, पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अरावली, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी, बोटाद और कच्छ में हल्की से भारी बारिश का अनुमान है।

6 अगस्त का पूर्वानुमान

राज्य में लगातार तीन दिनों तक दक्षिण गुजरात के इलाकों में भारी बारिश होगी. जिसमें मौसम विभाग की ओर से 6 अगस्त को नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है. इसके अलावा बनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा, पाटन, अरावली, खेड़ा, आनंद, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, डांग, सूरत, तापी, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, द्वारका, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ आदि में गरज के साथ अलग-अलग स्थानों पर हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है।

7-8 अगस्त का पूर्वानुमान

तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश के बाद 7-8 अगस्त को राज्य में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी. जिसमें उत्तर गुजरात में बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, अरावली, दक्षिण गुजरात में गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, तापी, नवसारी, डांग, नर्मदा, सूरत, वलसाड और राजकोट शामिल हैं। सौराष्ट्र के भावनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, अमरेली, मोरबी, गिर सोमनाथ, बोटाद, द्वारका जिलों में मध्यम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। पिछले 24 घंटों में गुजरात के 230 तालुकों में मेघ मेहर हुई है। जिसमें नवसारी के वांसदा में सबसे ज्यादा 7.24 इंच बारिश दर्ज की गई है. वघई में जहां 6.25 इंच रिकॉर्ड किया गया है, वहीं कपराडा, डोलवान और धरमपुर में करीब साढ़े पांच इंच बारिश हुई है. इसके साथ ही चालू मानसून सीजन में राज्य में औसतन 62 फीसदी बारिश हुई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 4 अगस्त तक दक्षिण गुजरात और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. उत्तर गुजरात. जिसमें बनासकांठा, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी जिलों के छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा जिले में मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी घोषित नहीं की गई है.

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है. जबकि 5 और 6 अगस्त को राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

तीन मंजिला इमारत का हिस्सा ढहने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

जामनगर (ईएमएस) शहर के साधना कॉलोनी में आज सुबह तीन मंजिला एक इमारत का एक हिस्सा ढहने से अफरा तफरी मच गई इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया इमारत में फंसे एक व्यक्ति का फायर विभाग के जवानों ने रेस्क्यू किया हादसे के बाद पूरी इमारत को खाली करा लिया गया हैं जानकारी के मुताबिक जामनगर के साधना कॉलोनी में सुबह-सुबह बड़ा हादसा हो गया। एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई जिस इलाके में यह घटना हुई वहां अफरा-तफरी मच गई स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के जवानों ने बचाव कार्य शुरू कर दी इमारत के मलबे में फंसे एक शख्स को फायर टीम ने बचा लिया हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस और नगर निगम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल जर्जर आवास को खाली करा लिया गया है। बता दें कि पिछले साल भी इसी इलाके में इमारत गिरने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी

सरदार पटेल गुड गवर्नेंस सीएम फेलोशिप के युवा फेलो के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार पटेल गुड गवर्नेंस सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में चयनित लगभग 18 आशास्पद व उत्साही सीएम फेलो युवाओं के साथ रविवार को संवाद करते हुए कहा, ''आपको अपने अभ्यास दौरान प्राप्त ज्ञान-कौशल का उपयोग सामाजिक जीवन एवं आम आदमी के कल्याण के लिए करने का एक उम्दा अवसर मिला है।'' इस संदर्भ में भूपेन्द्र पटेल ने कहा, ''यह अवसर आपके लिए तो लाभदायी होगा ही, साथ ही साथ सरकार के भावी नीति निर्माण व कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं सामाजिक जीवन में करोड़ों लोगों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुड गवर्नेंस की परंपरा से आम आदमी, गरीब, वंचित, सभी के कल्याण के लक्ष्य का जो शासन भाव विकसित किया है, उसे चरितार्थ करने में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में तेजस्वी व ओजस्वी युवाओं के इनोवेटिव्स आइडियाज की ऊर्जा के विनियोग के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह सरदार पटेल गुड गवर्नेंस सीएम फेलोशिप प्रोग्राम गत वर्ष 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती पर घोषित किया है। इस सरदार पटेल गुड गवर्नेंस सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के लिए प्राप्त आवेदनों में योग्यता के आधार पर लगभग 18 युवाओं का एक वर्ष के लिए फेलोशिप में चयन किया गया है। ये चयनित युवा सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) में प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण कर अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जन हितकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन, अध्ययन, डेटा एनालिसिस एवं इनोवेशन के लिए कार्यरत हुए हैं। राज्य सरकार ने इस प्रोग्राम में विश्वविख्यात मैनेजमेंट संस्थान भारतीय प्रबंध संस्थान-अहमदाबाद (आईआईएम-ए) को एकेडेमिक पार्टनर के रूप में जोड़ा है और यह संस्थान इन युवाओं को प्रशिक्षण के लिए मेंटर के रूप में सेवाएँ दे रहा है। सीएम फेलोशिप के ये युवा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए रविवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित रहे। भूपेन्द्र पटेल ने इन युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहा, ''गुजरात में श्रेष्ठ वातावरण है तथा आपके लिए फेलोशिप के रूप में कार्य करने में खुलापन भी है। योजनाओं के क्रियान्वयन या नए इनीशिएटिव्स लेने में फंडिंग की कोई समस्या नहीं है। आप श्रेष्ठ विचार व सुझाव लेकर आएँ। सरकार उन पर उचित ढंग से विचाराधीन रहेगी।'' उन्होंने जोड़ा कि ऐसे नए विचार अंततः तो राज्य के करोड़ों नागरिकों के भले के लिए लाभदायी ही बनेंगे। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इन युवा फेलो के साथ हर तीन महीने में एक समीक्षा बैठक आयोजित होनी चाहिए तथा उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहना चाहिए एवं उनके सुझाव भी सरकार को मिलते रहने चाहिए।

मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्य सचिव राज कुमार तथा मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी व श्री मनोजकुमार दास ने इन युवाओं को अपने-अपने सम्बद्ध विभागों में हाल में कार्य करने की जो अनुकूलता मिली है, उसके विषय में तथा उन्हें यदि कोई समस्या हो, तो वह बताने के लिए विषय में फेलो युवाओं के साथ खुले मन से चर्चा की। मुख्यमंत्री की सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह ने सीएम फेलोशिप की विस्तृत जानकारी दी और मुख्यमंत्री के फेलोशिप युवाओं का परिचय प्रस्तुत किया।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए 'मेक इन इंडिया' को अब 'मेड इन इंडिया' बनाना है : मुख्यमंत्री

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को अहमदाबाद में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (द इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी आईसीएसआई) के 51वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पाँचवें स्थान से तीसरे स्थान पर ले जाने की दिशा में अनेक प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कंपनी सचिव भी दे सकते हैं। भूपेन्द्र पटेल ने आगे कहा कि कोई भी कंपनी निरंतर आगे बढ़े तथा नियमित रूप से कर भुगतान करे, तो उसका लाभ देश को अवश्य मिलता है। आज देश के सभी नागरिकों को एक बात का अहसास हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था पाँचवें स्थान पर आने के बाद देश के छोटे से छोटे आदमी की प्रगति हुई है। इसलिए अब इस अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाने में सभी को योगदान देना है। वाइब्रेंट गुजरात समिट की सफलता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में गुजरात में दसवीं वाइब्रेंट गुजरात समिट का समापन हुआ है। इस समिट के कारण गुजरात को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि देश की 500 बड़ी कंपनियों में से लगभग 100 कंपनियाँ आज गुजरात में हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल कम्पीटिशन) का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आज केन्द्र सरकार व राज्य सरकार प्रत्येक वस्तु की गुणवत्ता पर बल दे रही है। प्रत्येक कंपनी को भी इस विषय पर अवश्य बल देना चाहिए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी को 'मेक इन इंडिया' को अब 'मेड इन इंडिया' बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 48 लाख करोड़ रुपए का बजट देश को आवंटित किया है। इस बजट में प्रत्येक सेक्टर को उसके अनुरूप योजनाबद्ध ढंग से वित्तीय आवंटन किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट देश के विकास में सुदृढ़ नींव डालने वाला बजट सिद्ध होने वाला है। भूपेंद्र पटेल ने माल एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी) की चर्चा करते हुए कहा कि अप्रैल महीने में 1.88 लाख करोड़ रुपए जीएसटी आय हुई है, जो देश के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस नीति के कारण सभी सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो लोग अच्छे ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। इस अवसर पर आईसीएसआई के अध्यक्ष बी. नरसिम्हन, उपाध्यक्ष धनंजय शुक्ला, अहमदाबाद चैप्टर के अध्यक्ष यश मेहता, सचिव जैमिन त्रिवेदी, कार्यक्रम निदेशक अलय वसावडा तथा बड़ी संख्या में कंपनी सचिव उपस्थित रहे।

जिग्नेश मेवाणी के इशारे पर मुझे परेशान किया जा रहा है - कांग्रेस की पूर्व महिला नेता आरोप

बनासकांठा (ईएमएस) वडगाम क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी पर कांग्रेस के पूर्व महिला नेता अरुणा परमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं अरुणा परमार का आरोप है कि जिग्नेश मेवाणी के इशारे पर उनके पीए सतीश वणसोला और शैलेष सोलंकी मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं सकलाणा गांव में मनरेगा के तहत काम करने वाली अरुणा परमार पहले वडगाम में कांग्रेस के एससी मोर्चा की प्रमुख थी अरुणा के मुताबिक उसके कांग्रेस छोड़ देने के बाद से जिग्नेश मेवाणी के इशारे पर उसे परेशान किया जा रहा हैं महिला ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर जिग्नेश मेवानी को उनके लोगों द्वारा बार-बार परेशान किया गया था। साथ ही महिला ने कहा कि अब मेरे पति जीवित नहीं हैं घर की सभी जिम्मेदारियां अब मुझ पर हैं महिला ने आरोप लगाया कि जिग्नेश मेवाणी के लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से टार्गेट कर रहे हैं। महिला ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि अब मैं यह अत्याचार सहन नहीं कर सकती, सभी भाई मुझे न्याय दिलाएं अरुणा परमार ने वडगाम पुलिस समेत जिला पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत कर उचित कार्यवाही की मांग की हैं

पेड की डाली काटने पर युवक को खंभे से बांधा फिर लाठियों से पीट पीटकर मार डाला
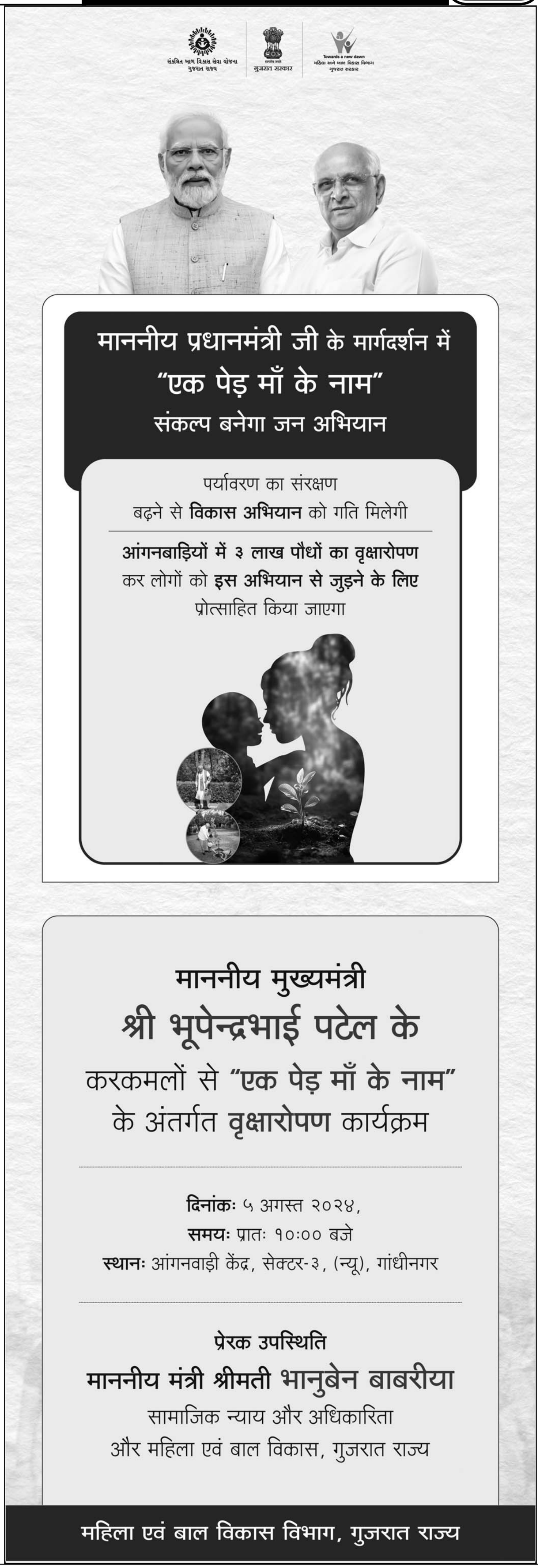
पंचमहल (ईएमएस) जिले के एक गांव से मामूली बात पर युवक को बिजली के खंभे से बांधने के बाद लाठियों से पीट पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया युवक का कसूर इतना था कि उसने नीम के पेड़ की एक डाली काटी थी, जिसके बदले में उसे तालीबानी सजा दी गई मृतक युवक की माता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की हैं यह घटना है पंचमहल जिले की शहेरा तहसीलके सराडिया गांव की जानकारी के मुताबिक सराडिया गांव निवासी 34 वर्षीय विजय पगी ने खेत की मेड पर लगे नीम के पेड़ की एक डाल काट दी थी बिस इतनी सी बात को लेकर विजय दूर के रिश्तेदार उसे उसके घर से घसीट कर ले गए और बिजली के पेड़ से बांध दिया इस पूरी घटना के दौरान विजय की माता गिड़गिड़ाती रही कि उसके बेटे को बख्श दो लेकिन आरोपियों से जैसे खून सवार था, उन्होंने विजय की बूढी मां की एक नहीं सुनी विजय को बिजली के खंभे से बांधने के बाद आरोपी पर लाठियां बरसाने लगे आरोपी विजय को तब तक पीटते रहे जब तक वह अधमरा नहीं हुआ खबर मिलते ही शहेरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और विजय को तुरंत अस्पताल के लिए रवाना कर दिया हांलाकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही विजय ने रास्ते में दम तोड़ दिया विजय की मां ने पुलिस को बताया कि मैं अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी और विजय को मेरी नजरों के सामने मौत के घाट उतार दिया बताया जाता है कि विजय अपनी माता के साथ रहता था और उनकी देखभाल करता था भोजन बनाकर अपनी माता विजय ही खिलाता हैं लेकिन मामूली बात पर वहशी दरिंदों ने वृद्ध माता का एक मात्र सहारा भी छीन लिया मृतक की माता की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया हैं